

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 577वीं बैठक दिनांक 11/06/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

**1. Case No 8624/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.082 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 6.082 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 12/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन व पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है, अतः समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि जब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया ओर अग्रेषित किया जाये।

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

- 2. Case No 8625/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 12/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन व पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है, अतः समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि जब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया ओर अग्रेषित किया जाये।

- 3. Case No 8626/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 12/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन व पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है, अतः समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि जब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया ओर अग्रेषित किया जाये।

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

- 4. Case No 8627/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.664 ha. (67968 cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.664 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 12/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन व पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है, अतः समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि जब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं हो जाता है तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती तथा प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया ओर अग्रेषित किया जाये।

- 5. Case No. – 6638/2019 Shri Rohit Kumar Agrawal, 47, Prabhat Vihar Colony, Panna Naka, Dist. Satna, MP, Prior Environment Clearance for Laterite and Ochre Mine in an area of 11.654 ha. (Laterite – 60,000 TPA, Ochre – 8,000 TPA) (Khasra No. 102P, 103P, 133P), Village - Pagar Kala, Tehsil - Birsinghpur, District Satna (MP). Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Laterite and Ochre Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 102P, 103P, 133P), Village - Pagar Kala, Tehsil - Birsinghpur, District Satna (MP) 11.654 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter No. 1443 dated: 01/05/19 has reported that there are no more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 410वीं दिनांक 02/12/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज का कुछ भाग शासकीय भूमि पर है तथा कुछ भाग निजी भूमि पर है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवेदित क्षेत्र रानीपुर अभ्यारण उत्तर प्रदेश की सीमा से 5820 मीटर की दूरी पर है तथा बिरसिंहपुर के वन क्षेत्र क्रमांक पी 872 की वन सीमा से 20 मीटर की दूरी पर है जिस कारण उनके द्वारा वन विभाग परिपत्र दिनांक 27/8/2008 के अनुसार अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लीज में से कुछ हिस्सा छोड़कर खनन की सहमति प्रदान की गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि वन्यप्राणी की सुरक्षा हेतु खदान के चारों ओर 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंग-फेंसिंग की जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में 08 पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम भाग से 15 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र के पश्चिम भाग से 60 मीटर की दूरी एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड़ के कारण प्रस्तावित 40 मीटर का सेट बेक मिलाकर नाले से दूरी 100 मीटर हो जायेगी तथा प्राकृतिक नाला के कारण गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किये गये हैं तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान परिवहन के दौरान सुरक्षा एवं मिनरल इवेक्वेशन रोड़ वृक्षारोपण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ आवंटित खदान निजी भूमि व शासकीय दोनों पर है, अतः विवरण दें कितना भाग निजी भूमि पर एवं कितना भाग शासकीय भूमि पर।
- ✓ खदान क्षेत्र पश्चिम भाग से 15 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 40 मीटर का सेट बेक प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र के पश्चिम भाग से 60 मीटर की दूरी एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड़ के कारण प्रस्तावित 40 मीटर का सेट बेक मिलाकर नाले से दूरी 100 मीटर हो जायेगी, अतः पुनरीक्षित सरफेस मेप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना।

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 10/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Laterite – 60,000 TPA, Ochre – 8,000 TPA मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.74 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 06.35 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
01	स्थानीय ग्रामीणों के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था की जायेगी ।	30,000 / –
02	ग्राम पगार कलां के प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चों को बैग, जूते टिफिन, बॉक्स का वितरण किया जायेगा ।	30,000 / –
03	उज्ज्वला योजना के तहत आसपास के गांवों में रहने वाले 10 खदान कर्मियों को सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया जायेगा ।	20,000 / –
03	ग्राम पगार कलां के आगनवाडी में पोषण आहार का वितरण किया जायेगा ।	20,000 / –
	<b>(आगामी एक वर्ष तक) योग</b>	<b>1,00,000 / –</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 13,500 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा ।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन (शासकीय भूमि) (प्रथम वर्ष)	महुआ, सिस्सू, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	2600
2	बैरियर जोन (निजी भूमि) (द्वितीय वर्ष)	जामुन, बैर, मुनगा, आंवला, इमली, सीताफल, आम, महुआ अन्य फलदार प्रजातियाँ ।	1400
3	पगार कलां के शासकीय विद्यालय में (प्रथम वर्ष)	कचनार, पुत्रंजीवा, अमलतास, सीता अशोक, नीम, गुलमोहर आदि ।	20
4	वन क्षेत्र और खनन क्षेत्र की सीमा के बीच में । ( द्वितीय वर्ष)	शीशम, नीम, चिरौल, पीपल, बरगद, खमैर, सीताफल, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	5980

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

5	ग्रामपंचायत पगार कलां के ग्रामवासियों को वितरण हेतु (प्रथम वर्ष)	इमली, आवंला, आम, अमरुद, करोंदा, सीताफल, महुआ, मुनगा, कठल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	3000
6	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	नीम, पीपल, महुआ, बरगद, खमैर, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
कुल			13,500

**6. Case No 9201/2022 M/s Vindhya Mining Works, Partner, Shri Brajesh Kumar Singh, 9F, H-3, 154, Sector - 9, Obra, Dist. Sonbhadra, UP - 231219, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (18125 Cum per annum) (Khasra No. 827), Village - Gangi, Tehsil - Chitrangi, Dist. Singrauli (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 827), Village - Gangi, Tehsil - Chitrangi, Dist. Singrauli (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 11/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**7. Case No 9202/2022 Shri Ram Sakha Verma Owner, Village - Sandoh, Tehsil - Teonthar, Dist. Rewa, MP - 486220 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (14999 Cum per annum) (Khasra No. 79 (Part)), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79 (Part)), Village - Sardaman, Tehsil - Hanumana, Dist. Rewa (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज दिनांक 11/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**8. Case No 9203/2022 M/s Balaji Granite, Partner, Smt. Renu Singhal, 502, Satyam Residency Tower, Alkapuri Tirha, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.024 ha. (21850 Cum per annum) (Khasra No. 49/1, 49/2, 50), Village - Berja, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 49/1, 49/2, 50), Village - Berja, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) 1.024 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9789 दिनांक 20/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.876 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 42 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के अंदर 03 शेड विद्यमान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पश्चिमी भाग खुदा हुआ है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार 2013 से खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व निकाले गये खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये हैं तथा सरफेस मैप पर गड्ढा दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के अंदर 03 शेड विद्यमान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 42 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**9. Case No 9207/2022 Shri Manish Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Project Proponent, Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP, Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 14.40 ha. (4500 Cum per annum) (Khasra No. 570), Village - Bagrohi, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP)**

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 570), Village - Bagrohi, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) 14.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1042 दिनांक 11/07/2019 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 17.40 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र में क्रमशः 110 एवं 100 मीटर पर आबादी है



## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से लीज के अंदर से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । इसी प्रकार खदान के पूर्वी क्षेत्र में 40 मीटर दूरी पर तथा पश्चिम क्षेत्र से 60 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । खदान के पश्चिमी भाग के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है अतः माईन वाटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करे । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र में क्रमशः 110 एवं 100 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से लीज के अंदर से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
4. खदान के पूर्वी क्षेत्र में 40 मीटर दूरी पर तथा पश्चिम क्षेत्र से 60 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
5. खदान के पश्चिमी भाग के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है अतः माईन वाटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

### **10. Case No 9208/2022 Shri Mukul Purohit S/o Shri Balkrishna Purohit, Project Proponent Bhagat Singh Ward, Dist. Sagar, MP, Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 10.0 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 312, 315, 323), Village - Shahgarh, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP)**

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 312, 315, 323), Village - Shahgarh, Tehsil - Shahgarh, Dist. Sagar (MP) 10.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

आज दिनांक 11/06/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 11/07/2019 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 11.68 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र में 50 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। खदान के बीच से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये। खदान के मध्य भाग के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है अतः माईन वाटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व एवं उत्तरी क्षेत्र में 50 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. खदान के बीच से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये।
4. खदान के मध्य भाग के क्षेत्र में पानी भरा हुआ है अतः माईन वाटर डिस्चार्ज प्लॉन ई.आई.ए. के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

**11. Case No 9190/2022 Shri Pankaj Joshi, 2/14, Jharenshtar Complex, Jawahar Chowk, New Market, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) EIA Consultant: Congnizance Research India (P) Ltd., Noida (UP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 20/1 Part), Village - Leelakhedi, Tehsil - Sehore, Dist. Sehore (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

**12. Case No 9171/2022 Shri Kishan Singh Chouhan, Owner, Village - Sada, Tehsil - Bahoribandh, Dist. Katni, MP - 483331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

**13. Case No. - 5750/2018 M/s K. L. Sharma, Regal Homes, 157, C-Sector, Indrapuri, Bhopal, (M.P.) – 462026. Prior Environment Clearance for Construction of Residential & Commercial Project "Regal Town" (Total Plot Area = 27,860 sqm., Built up Area = 49,678.50 sqm) at Village - Khajuri Kalan, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.) Category: 8(a) Building & Construction Project. (Violation).**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Construction of Residential & Commercial Project "Regal Town" (Total Plot Area = 27860 sqm., Built up Area = 49678.50 sqm) at Village - Khajuri Kalan, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.) Cat. 8(a) Building and Construction Projects. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर से डॉ. यशवंत मिश्रा उपस्थित हुए तथा समिति को जानकारी दी कि परियोजना प्रस्तावक श्री के.एल.शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे प्रस्तुतीकरण में उपस्थित नहीं हो पाये। डॉ. मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा रेमिडिएशन तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी रिसोर्स अगमेंटेशन प्लॉन से संबंधित कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को वापिस करने के अनुरोध के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नियमानुसार भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कम्पलाइंस रिपोर्ट पत्र क्रमांक 856 दिनांक 31/12/21 के द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है।

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

समिति द्वारा भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा सर्टिफाईड कम्पलाइंस रिपोर्ट पत्र क्रमांक 856 दिनांक 31/12/21 का अवलोकन किया गया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करें :—

- अ. आवेदक ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल की निरीक्षण के दौरान उनको अवगत कराया था कि उनके द्वारा 5511 वर्गमीटर क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें 1182 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा । अतः इस क्षेत्र में आज दिनांक तक कितने पौधों लगाये गये हैं, उनकी प्रजातिवार सूची मय फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत करें ।
- ब. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु 07 रिचार्ज पिट बनाये जाने थे तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल की निरीक्षण के दिवस तक सिर्फ 02 पिट ही बने थे । अतः आज की स्थिति में कितने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट बन गये हैं तथा यदि कुछ बनने बाकी हैं तो क्या योजना है से अवगत करायें ।
- स. सोलर एनर्जी के उपयोग के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किये गये हैं, का विवरण प्रस्तुत करें ।

**13. Case No 9159/2022 M/s Vijay and Company, Partner Shri Anshuman Rai, Rai Bhawan, Katni Road, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, MP - 485771 Prior Environment Clearance for Stone / M-Sand Quarry in an area of 3.610 ha. (85500 Tonne per annum) (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP)**

This is case of Stone / M-Sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 3.610 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2896 दिनांक 22/11/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 65 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

बताया कि यह पगडंडी है, कच्चा रास्ता नहीं है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सैंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लॉन page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-14.6 में Ground Water Table From 0.97 To 16.9, (डिस्ट्रिक्ट ग्राउण्ड वाटर इंफारमेशन बुकलेट अनुसार डेटा वर्ष 2012 का है), अतः परियोजना प्रस्तावक वर्तमान Ground Water Table डेटा उपलब्ध करायें ।
- ✓ एम-सैंड प्लांट की लोकेशन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप तथा एम-सैंड प्लांट का ले-आउट ।
- ✓ एम-सैंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी., वृक्षारोपण एवं सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 02/06/22 को अपलोड किया गया । प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है क्योंकि रिवाइज फार्म-2 में जानकारी चाही गई थी किंतु परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-2 के स्थान पर पी.एफ.आर. प्रस्तुत की है । अतः परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी पुनः प्राप्त की जाना प्रस्तावित है :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सैंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लॉन page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ एम-सैंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।

### **14. Case No 9106/2022 Shri Nishant Jaiswal, Leasee, Mohad Stone Deposit, R/o Bhikangaon, Dist. Khargone, MP -451332 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (5044 cum per annum) (Khasra No. 152/1), Village - Mohad, Tehsil - Jhirniya, Dist. Khargone (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 152/1), Village - Mohad, Tehsil - Jhirniya,

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

Dist. Khargone (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि यह प्रकरण पूर्व आवेदन क्रमांक 8810/2021 के द्वारा सिया से सेक को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भेजा गया था । उक्त प्रकरण को समिति की 531वीं बैठक दिनांक 06/12/21 तथा 545वीं दिनांक 29/01/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है । सिया की 706वीं बैठक दिनांक 16/02/22 में प्रश्नाधीन खदान के 100 मीटर की दूरी पक्की सड़क होने के कारण न्यूनतम् खनन् क्षेत्र उपलब्ध नहीं होना परिलक्षित है, के प्रकाश में पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन को निरस्त का निर्णय लिया गया है ।

इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-2 के सरल क्रमांक-8.1 में एवं पी.एफ.आर में उत्खनन विधि के अंतर्गत रॉक ब्रेकर का उपयोग का उल्लेख करते हुए पुनः आवेदन किया गया, जिसे सिया द्वारा ऑनलाईन परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया ।

सेक की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव ऑनलाईन उपस्थित हुए । एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 17/09/21 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 150 मीटर पर जलीय निकाय है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर रोड़ तथा दक्षिण-पूर्वी दिशा में 150 मीटर पर नदी है । इसी प्रकार खदान के पश्चिम दिशा में 170 मीटर तथा पूर्व दिशा में 85 मीटर पर नहर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि पूर्व की गूगल इमेज 2014-15 से यदि खनन् स्थल का अवलोकन किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि खनन् क्षेत्र को बीच से काटता हुआ एक मौसमी नाला (दक्षिण-पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर) निकल रहा है । समिति ने चर्चा उपरांत यह पाया कि यदि इस नाले से दोनों ओर 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये तो खनन् हेतु उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा अतः यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा योग्य नहीं है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये ।

सिया की 722वीं बैठक दिनांक 07/05/22 को परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 07/05/22 के साथ संलग्न कलेक्टर खनिज शाखा जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 7642 दिनांक 05/05/2 में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग, राजस्व विभाग तथा खनि निरीक्षण के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में कोई मौसमी नाला वर्तमान में स्थित नहीं है । अतः माननीय एन.जी.टी. के ओए नं. 304/2019 अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लस्टिंग तथा ब्लस्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी के स्थानवार तय मापदण्ड का परिपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उक्त प्रकरण को पुनर्परीक्षण हेतु सेक को भेजा गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि पूर्व की गूगल इमेज 2014-15 से यदि खनन् स्थल का अवलोकन किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि खनन् क्षेत्र को बीच से काटता हुआ एक मौसमी नाला (दक्षिण-पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर) निकल रहा है एवं बाद की गूगल इमेज में यह मौसमी नाला नहीं दिखता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कलेक्टर खनिज शाखा जिला

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

खरगौन के पत्र क्रमांक 7642 दिनांक 05/05/22 में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग, राजस्व विभाग तथा खनिज निरीक्षण के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में कोई मौसमी नाला वर्तमान में स्थित नहीं है एवं यदि समिति चाहे तो स्थल का निरीक्षण कर निर्णय ले सकती है। अतः समिति ने यह निर्णय लिया कि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण जून, 2022 के प्रथम सप्ताह तक किया जाये तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

समिति के सदस्य डॉ. रूबीना चौधरी द्वारा दिनांक 09/06/22 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक क्रमांक 572 दिनांक 19/05/2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण क्रमांक 9106/2022 (Shri Nishant Jaiswal S/o Shri Arvind Jaiswal, Bhikangaon, Dist. Khargone, MP -451332, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (5044 cum per annum) (Khasra No. 152/1), Village - Mohad, Tehsil - Jhirniya, Dist. Khargone (MP) का निरीक्षण दिनांक 09/6/22 को किया गया जिसके दौरान निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. डॉ. रूबीना चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, म.प्र.।
2. डॉ. अभय कुमार सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल।
3. श्रीमती रीना पाठक, खनिज निरीक्षण, जिला खरगौन।
4. श्री अब्दुल रजाक कुरैशी, तहसीलदार, तहसील झिरनिया।
5. श्री निशांत जैसवाल, परियोजना प्रस्तावक।

निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कलेक्टर, खनिज शाखा, खरगौन ने पत्र क्रमांक 7642/खनिज/22, दिनांक 05/05/22 के माध्यम से बताया गया है कि वन विभाग, राजस्व विभाग तथा खनिज निरीक्षक के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र में कोई नाला वर्तमान स्थिति में नहीं है जो इस रिपोर्ट के संलग्नक-दो पर संलग्न है।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित खनिज निरीक्षण, जिला खरगौन, श्रीमती रीना पाठक ने बताया कि उपरोक्त खदान की स्वीकृति एम.एम.आर., 1996 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप की गई है तथा खदान के पास बह रही नदी के कारण कम से कम 150 मीटर का सेफ जोन खदान के आसपास छोड़ा गया है।

स्थल निरीक्षण के दौरान एक पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीण श्री तेजू, ग्राम मोहड, तहसील झिरनिया, श्री मदन, ग्राम देविदखुर्द, तहसील झिरनिया तथा श्री सतीस, ग्राम मोहड, तहसील झिरनिया से भी इस संदर्भ में पूछताछ की गई तथा उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि आवेदित क्षेत्र में कोई नदी/नाला नहीं है। स्थल पंचनामा रिपोर्ट के संलग्नक-एक पर संलग्न है।



## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

उपरोक्त खदान के स्थल निरीक्षण में पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के कुछ भाग में ऊपर तक पत्थर निकला हुआ है तथा कुछ भाग में खेती की जमीन है जिस पर टॉपस्वाइल मौजूद है। यह खदान नदी से करीब 150–200 मीटर की दूरी पर है तथा आवेदित क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में कोई नदी / नाला नहीं हैं लेकिन वर्षा के दौरान वर्षा जल के सरफेस रनऑफ के रूप में इस खदान से बहकर जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सरफेस रनऑफ के कारण आवेदक को गारलेण्ड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की व्यवस्था की जाना चाहिए। स्थल निरीक्षण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा जो प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, उसमें गारलेण्ड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है तथा आवश्यक बजट भी ई.एम.पी. में दिया गया है।

समिति के बैठक के दौरान डॉ. रुबीना चौधरी ने निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों से समिति को अवगत कराया। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव ई.एम.पी. में दिया है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,044 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.75 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

क्रं.	सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
1.	ग्राम मोहद के आगनवाडी में पोषण आहार का वितरण।	50,000 / –
	<b>(आगामी एक वर्ष तक) योग</b>	<b>50,000 / –</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सीताफल, करंज अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	900

**577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 11 जून 2022**

2.	मोहद के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, बेल, आँवला, कैथा, आम, अमरुद एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	1200
3.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	नीम, बबूल, चिरोल, कचनार, अमलतास, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	190
4.	मोहद के विद्यालय में	पुत्ररंजीवा, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	20
कुल			2400

(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

### **Annexure- 'A'**

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.  
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 11 जून 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain



## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 11 जून 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - I. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 577वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 जून 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained